

उत्तराखण्ड में सख्त भूमिकानून

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सख्त भूमिकानूनों को लागू करने की संभावना है, जिससे गैर-मूल नवासियों के लिये राज्य की पहाड़ियों के ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीदना और अपना घर बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

मुख्य बटु :

- **हमिाचल प्रदेश करिायेदारी और भूमिसुधार अधनियिम, 1972** से प्रभावति प्रस्तावति कानून का उद्देश्य ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि अधग्रहण को सीमति करके राज्य के हतियों की रक्षा करना है।
- वर्ष 2003 में, बाहरी लोगों को पहाड़ी इलाकों में 500 वर्गमीटर की सीमा के साथ ज़मीन खरीदने की अनुमति दी गई।
 - बाद की सरकारों ने बड़े पैमाने पर भूमिलेनदेन को रोकने के लिये इस सीमा को घटाकर 250 वर्गमीटर कर दिया।
- वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंतरी त्रविन्दर रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में नविश आकर्षति करने के लिये इन प्रतबिंधों को हटा दिया था।
- वभिन्नि ज़िलों में वरिोध प्रदर्शन के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में पूर्व मुख्य सचवि की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा प्रस्तुत मसौदा रपिोर्ट का अध्ययन करने के लिये पाँच सदस्यीय समति का गठन किया।
 - रपिोर्ट में राज्य के संसाधनों का दोहन करने वाले बाहरी नविशकों की चतिाओं को संबोधति करते हुए शहरी क्षेत्रों में भूमि खरीद की सीमा तय करने की सफिारशि की गई है, जिससे पहाड़ियों में भूमिलेनदेन के लिये 12.5 एकड़ की सीमा को बहाल किया जा सकता है।
 - हालाँकि, नविासी इसका समर्थन कर रहे हैं, जिसमें नगरपालिका क्षेत्रों की सीमा 250 वर्गमीटर तक करना और ग्रामीण भूमि की बकिरी पर पूर्ण प्रतबिंध लगाना शामिल है।